'नीतीश व चन्द्रबाबू की बैसाखी पर टिकी है दिल्ली की सरकार'

सचिन पायलट ने कहा कि एक भी बैसाखी खिसक गई तो सरकार धराशायी हो जायेगी

- पायलट ने उदयपुर में रघुवीर मीणा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रघुवीर मीणा अशोक गहलोत के नज़दीकी रहे हैं। सलुम्बर उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर वे गहलोत से नाराज हैं। अब वे पायलट के साथ नज़र आ रहे हैं।
- पायलट ने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाने जा रही है, इसलिए जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने गहलोत के नज़दीकी रहे पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उदयपुर, (कासं), 5 मई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों में 300 और 400 पार की बात करने वाले 240 पर अटक गए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दो बैसाखियों में से एक बैसाखी खिसक गई, उसी दिन सरकार धराशायी हो जाएगी।

उदयपुर प्रवास पर आये पायलट ने सोमवार को गहलोत के नजदीकी रहे पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार डेढ़ साल से राज कर रही है लेकिन राजस्थान में नौकरियों और भर्तियों में जो फर्जीवाड़े हुए हैं, उनमें कितने लोगों को अब तक पकड़ा है। छोटे-मोटे लोगों को पकड़कर छोड़ दिया है। प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए। पायलट बोले, यहां पर अफसरशाही हावी है। जो वायदे किए हैं, भर्तियों के करप्शन को लेकर और आरपीएससी से जुड़े हुए, उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए। लगता है कि सरकार पर भी दबाव होगा। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी रहे रघुवीर मीणा सलूम्बर उप चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर नाराज हुए थे। इसके बाद अब वे पायलट के साथ नजर आए हैं।

सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा को जुमला देने की बहुत पुरानी आदत है। पहले जुमला दिया था महिला आरक्षण का, लेकिन कब लागू होगा, पता किसी को नहीं। बाप विधायक के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर पायलट ने कहा कि राजस्थान में पहली बार इस तरह की घटना हुई है।

पायलट ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति कहीं कमजोर नहीं है। हर गांव, ढाणी में कांग्रेस का समर्थक वोटर मौजूद है। उदयपुर संभाग में कांग्रेस का विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया था। पार्टी पूरे देश में जिलाध्यक्षों को और ताकत देना चाहती है।

जातिगत जनगणना के सवाल पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस इस मांग को बहुत लंबे समय से उठा रही है। हम चाहते हैं कि समय सीमा बांधकर जातिगत गणना के कार्यक्रम को तैयारी से लेकर आएं।

पहलगाम हमले पर सचिन बोले कि बिना समय गंवाए सरकार को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर आज भी खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जो कदम उठाए, उसको पूरा समर्थन है।

सी.बी.आई. के नए निदेशक के चयन के लिए मीटिंग

नयी दिल्ली, 05 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नये निदेशक का नाम तय करने के लिये सोमवार को यहां चयन समिति की बैठक हुई।

प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी

- प्र.मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सी.जे.आई. संजीव खन्ना व नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी भी शामिल हुए।

शामिल हुये। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सीबीआई निदेशक का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होना अनिवार्य है और न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि इस पद पर उसी अधिकारी के नाम पर विचार किया जा सकता है, जिसका सेवाकाल कम से कम छह माह जरूर बचा हो।

गृहमंत्रालय ने राज्यों से 7 मई को सिविल डिफैंस मॉक ड्रिल करने को कहा

पिछली बार ऐसी मॉकड्रिल 1971 में हुई थी, तब भारत-पाक युद्ध हुआ था

- इस मॉक ड्रिल में लोगों को हवाई हमले से अपना व अन्य लोगों का बचाव करना सिखाया जाएगा और हमले के समय सायरन बजने तथा ब्लैक आउट के बारे में भी अभ्यास कराया जाएगा।
- रविवार की रात को पंजाब के फिरोज़पुर में ब्लैक आउट प्रैक्टिस की गई, गांवों व मोहल्लों में रात 9 से 9.30 बजे बिजली बंद रही।

नई दिल्ली, 05 मई। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों से, हमले की स्थिति में बचाव की तैयारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने को कहा है।

सूत्रों के अनुसार.मंत्रालय ने राज्यों से परसों, यानी सात मई को यह मॉक ड्रिल करने को कहा है।

मॉक ड्रिल में लोगों को, विशेष रूप से हवाई हमले के समय, अपना और अन्य लोगों का बचाव करने की जानकारी देने के साथ-साथ, अभ्यास कराया जाएगा। लोगों को हमले के समय सायरन बजने और ब्लैक आउट के बारे में बताया जाएगा। यह ड्रिल नागरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए की जाएगी, जिसका उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उल्लेखनीय है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। इस हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की जघन्य हत्या कर दी थी। भारत ने कहा है कि इस हमले के दोषी आतंकवादियों और उनकी सहायता तथा समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी।

रविवार-सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांवों और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही।

मॉक ड्रिल के दौरान सबसे पहले, एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया जाएगा। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं। इसके साथ ही क्रैश ब्लैक आउट के उपाय किए जाएंगे। अर्थात्, हमले के दौरान रोशनी बंद करने, यानी क्रैश ब्लैक आउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए, यह बताया जाएगा।

निकासी योजना, अर्थात इवैकुएशन प्लान क्या होगा, इस बारे में लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही, इवैकुएशन अभ्यास भी किया जाएगा। इवैकुएशन प्लान का मतलब है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना, अर्थात युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को सुरक्षित जगह ले जाएं, इसकी तैयारी की जाएगी।

'जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई दिल्ली जिसे सीमा पार से स्थायी आतंकी अभियान के रूप में देखती है, उसे पूरी तरह निष्प्रभावी कर देने के लिए, विभिन्न मोर्चों और विकल्पों को खंगाल रही है, जिनमें शामिल हैं - कूटनीति दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, साइबर वॉरफेयर क्षमताएं तथा क्रॉस-बॉर्डर इनटेलिजेंस ऑपरेशन।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भी संकेत दिया है कि वैश्विक ताकतों, खासतौर से अमेरिका, फ्रांस तथा रूस, के साथ कूटनीतिक सम्पर्क तेज किए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को अलग-थलग किया जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उसे जवाबदेह ठहराया जा सके।

चूंकि इस समय तनाव चरम पर है, इसलिए जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती चौकियों पर सेना चुस्त-दुरूस्त कर दी गई है तथा सैनिकों की तादाद बढ़ा दी गई है तथा किसी प्रकार की घुसपैठ के प्रयासों या हमलों को निष्फल करने के लिए खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर कर दी गई हैं।

जहां जनता की भावनाएं तत्काल बदले की मांग कर रही हैं, वहीं भारतीय नेतृत्व दूरगामी प्रभाव वाला खेल खेलता प्रतीत हो रहा है तथा किसी संभावित सैन्य टकराव में उलझने के बजाय, सीमा-पार के आतंकवाद के मूल कारणों को ध्वस्त करने पर फोकस कर रहा है।

इस समय, भारत प्रतीक्षा की मुद्रा में है, लेकिन अटल संकल्प के साथ। साउथ ब्लॉक का स्पष्ट संकेत है : अगर, और जब भी, प्रतिशोध लिया जायेगा, वह भारत की शर्तों पर लिया जायेगा और वह सुविचारित, व्यापक और अधिकतम प्रभावी होगा।

विधायक पटेल के रिश्तेदार ने 20 लाख रुपये जमीन में गाड़ दिये थे

ए.सी.बी. ने प्रताप नगर इन्दिरा गांधी नगर के मकान में जमीन में दबी राशि बरामद की

- वकीलों की हड़ताल के कारण पुलिस विधायक को पैदल लेकर कोर्ट पहुंची।

जयपुर, 5 मई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बागीदौरा विधानसभा जिला बांसवाड़ा के भारत आदिवासी पार्टी (बाप) विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्वत में लिए बीस लाख रुपए बरामद कर लिए। जानकारी में सामने आया कि विधायक ने पैसा भांजे को दे दिया था और भांजे ने पैसे रिश्तेदार को दे दिए। रिश्तेदार ने यह पैसे जमीन में गाड़ दिए। एसीबी टीम ने जमीन में दबे रुपए निकाल लिए।

एसीबी पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी जांच में सामने आया है कि विधायक पटेल ने रिश्वत की यह रकम अपने भांजे रोहित को सौंपी थी। जिसने रकम को आगे रिश्तेदार जसवंत को सौंप दिया। जसवंत ने रकम को अपने परिचित जगराम को सौंप दिया और पैसे को जमीन में छिपाने के लिए कहा। जहां एसीबी की टीम ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर जसवंत को ट्रेस कर हिरासत में लिया। करीब ढाई घंटे की पूछताछ में जसवंत ने खुलासा किया कि रकम जगराम के पास है। इसके बाद एसीबी टीम जगराम के प्रतापनगर, इंदिरा गांधी नगर स्थित घर पहुंची और वहां से जमीन में दबे हुए 20 लाख रुपए बरामद कर लिए।

पूछताछ में यह भी सामने आया कि रिश्वत की यह राशि एक प्रॉपर्टी डीलिंग के बहाने ली गई थी। लेकिन सौदा नहीं हुआ। इसलिए जगराम को पैसे छिपाने के निर्देश दिए गए थे। एसीबी की टीम विधायक जयकृष्ण को लेकर एसीबी कोर्ट पहुंची। वकीलों की हड़ताल होने के कारण विधायक को पैदल लाया गया था। इधर विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विधायक और उसके चचेरे भाई को दो दिन की रिमांड पर सौंप दिया। इसके बाद एसीबी टीम विधायक को मुख्यालय लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ एसीबी ने विधायक आवास के सभी सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। सर्वर रूम की एफएसएल से जांच करवाई जाएगी।

गौरतलब है कि एसीबी ने रविवार को कार्रवाई करते हुए बागीदौरा विधानसभा जिला बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के विधायक जयकृष्ण पटेल और दलाल विजय कुमार पटेल को बीस लाख रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के विधायक जयकृष्ण ने विधानसभा में खनन विभाग से संबंधित उठाए गए सवालों को वापस लेने के लिए 10 करोड़ की डिमांड की थी और बाद में 2.5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। जब एसीबी टीम विधायक के आवास पर पहुंची थी तो एक व्यक्ति ये रुपए लेकर भाग गया था।

ए.सी.बी. कोर्ट ने विधायक और दलाल को सौंपा दो दिन के रिमांड पर

जयपुर, 5 मई। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने विधानसभा में लगाए गए सवाल को वापस लेने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार बांसवाड़ा के बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल और उसके चचेरे भाई व दलाल विजय कुमार उर्फ विक्की को दो दिन के पुलिस रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। एसीबी की ओर से दोनों आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया। एसीबी ने रिश्वत की बीस लाख रुपए की राशि बरामद करने सहित अन्य बिंदुओं पर आरोपियों की चार दिन की पुलिस रिमांड मांगी। इस पर अदालत ने दोनों को सात मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। एसीबी ने रविवार 4 मई को विधायक जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार किया था। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता रविन्द्र सिंह ने गत चार अप्रैल को एसीबी अधिकारियों को विधायक के बारे में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि विधायक ने खनन को लेकर विधानसभा में कुछ सवाल लगाए थे। इन्हें वापस लेने की एवज में विधायक ने पहले उससे दस करोड रुपए मांगे, वहीं बाद में सौदा 2.5 करोड रुपए में तय हुआ। शिकायत पर एसीबी ने उसका सत्यापन कराया, जिसमें विधायक बार-बार शिकायतकर्ता को फोन कर पैसा देने को कहा रहा था। वहीं 3 मई रात को विधायक ने फोन कर शिकायतकर्ता को 4 मई सुबह जयपुर में मिलने को कहा। सुबह करीब 11.30 बजे शिकायतकर्ता पैसा लेकर विधायक आवास पहुँचा। शिकायतकर्ता ने कार में ही विधायक को रुपए दिए, जिनको विधायक ने कार में बैठकर गिना। इसके बाद विधायक ने पैसा किसी अन्य व्यक्ति को दिया, जो पैसा लेकर निकल गया। एसीबी ने विधायक को उसी दौरान डिटेन कर उनके हाथ धुलाए गए तो उसके हाथ लाल हो गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल विधायकों के साथ गुड गवरनैंस कैंप के लिए गुजरात पहुँचे

इस प्रशिक्षण शिविर को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा व गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे

- नर्मदा जिले में प्रवेग टेंट सिटी में राजस्थान के सभी विधायक व सांसद भाग ले रहे हैं। कैंप में सत्ता-संगठन समन्वय, जनता से संवाद तथा पार्टी की रीति-नीति के अनुरूप कार्यशैली सिखायी जायेगी।

जयपुर, 5 मई। राजस्थान के सभी भाजपा सांसद और विधायक अब सुशासन का पाठ पढ़ेंगे। इसके लिए गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित प्रतिष्ठित प्रवेग टेंट सिटी में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत आज से होगी। जिसे भाजपा ने "सुशासन कांफ्रेंस" नाम दिया है। यह शिविर 5 मई से 7 मई तक चलेगा। पहले दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायकों और सांसदों को संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण शिविर का मकसद जनप्रतिनिधियों को सत्ता-संगठन समन्वय, सुशासन की अवधारणा, जनता से संवाद और पार्टी की नीति के अनुरूप कार्यशैली सिखाना है।

कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए प्रदेश के सभी सांसद और विधायक गुजरात पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चार्टर्ड प्लेन से, 40 से ज्यादा विधायक सांसद फ्लाइट से और शेष सांसद और विधायक अपने निजी वाहनों से कॉन्फ्रेंस से भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक दिन पहले ही अहमदाबाद पहुंच गए हैं। कॉन्फ्रेंस 7 मईशाम 5 बजे समाप्त होगी।

बताया जा रहा है समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर सकते हैं। तीन दिन चलने वाली सुशासन कांफ्रेंस में विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 5 मई को शाम 6 बजे सबसे पहले स्वागत सत्र होगा। जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इस कार्यशाला के सभी सत्रों में विधायकों का रहना अनिवार्य किया गया है।

कार्यशाला में सभी सांसद-विधायकों को सुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को गुजरात में ट्रेनिंग मिलेगी। पार्टी की रीति-नीति के अनुरूप कार्यशैली का पाठ सिखाया जाएगा।

कैंप में तीन दिन तक सत्ता संगठन समन्वय, जनता समन्वय, सुशासन की अवधारणा, पार्टी की रीति-नीति के तहत जनता की सेवा आदि विषय पर राष्ट्रीय नेता अपना अपना संबोधन देंगे। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के 139 सांसद और विधायकों में से 137 विधायक और सांसद भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं।

पंचायत और निकाय चुनाव संभावित हैं। सत्ता में रहते हुए भाजपा की रणनीति है कि ग्रामीण स्तर पर पकड मजबूत की जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को योजनाओं के प्रचार-प्रसार और पात्र लाभार्थियों तक योजनाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिये पार्टी राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारी भी करेगी।

एस.आई.भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी ने कहा कि मामले में ईडी प्रारंभिक जांच कर रही है। जेल में बंद दो आरोपियों के भी जल्द ही बयान दर्ज किए जाएंगे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समान मुद्दे पर बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द किया है। अदालत ने एसआई भर्ती पर निर्णय करने के लिए राज्य सरकार को पहले ही दो माह का समय दे दिया है। सरकार को अब और समय नहीं दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर निर्णय करने के लिए राज्य सरकार को 15 मई तक का समय दिया है।

वक्फ मामलों की सुनवाई नए सी.जे.आई. की खंडपीठ करेगी

नयी दिल्ली, 05 मई। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं के कुछ विवादास्पद मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि पूरे मामले की मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 15 मई को सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने विवादास्पद मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार द्वारा देश की वक्फ संपत्तियों के रूप में पेश किए गए 3921236.459 एकड़ भूमि के आंकड़े पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, जिस पर दूसरे पक्षों द्वारा आपत्ति की जा रही है। हालांकि, 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि वह अंतरिम चरण में भी इस मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे, इसलिए मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। नामित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

पीठ ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा, हमने जवाबी दलीलों पर गौर किया है। हां, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ मुद्दों पर सवाल उठाए गये हैं, और याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां दर्ज की हैं। इन पर विचार किए जाने की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। यह मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष रखेंगे।

'अपने चैनल पर पाकिस्तानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर भी मीडिया के उस वर्ग में सवाल उठ रहे हैं, जो सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर आशंकित है। एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि यह एडवायज़री एक तरह से सैंसरशिप का संकेत है, खासकर पहलगाम हमले में हुई सुरक्षा चूक के बाद। प्रैस की आज़ादी व कूटनीति पर एडवायज़री के परिणामों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।

'राजनीतिक आधार पर सरकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखते हुए की जाए तो इससे न्याय में तेजी आएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता से अदालत ने पूछा कि क्या समान मामले में पूर्व में कोई याचिका पेश हुई थी? इस पर एजी ने कहा कि एक प्रकरण जोधपुर मुख्यपीठ और एक प्रकरण जयपुर पीठ में लंबित चल रहा है। इस पर अदालत ने दोनों प्रकरणों में दिए आदेशों की कॉपी पेश करने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है।

आई.एम.एफ. के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आया है, उसको धक्का लगेगा।

इसका असर वित्तीय बाजारों की मौजूदा तेजी पर भी पड़ सकता है, जिससे भारत में विदेशी निवेश की आवक धीमी हो सकती है। ट्रंप की "चीन को अलग-थलग करने" की नीति और चीन केन्द्रित सप्लाई चेन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के प्रयासों के कारण भारत को बड़ा लाभ मिल रहा है। वास्तव में, अब भारत में मैन्युफैक्टरिंग केन्द्र स्थापित करने में देशों की रुचि बढ़ रही है, और भारत, चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तुलना में उत्पादन के लिए बेहतर विकल्प बन रहा है।

रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत कश्मीर के पहलगाम हमलों के बाद युद्ध और आंतरिक अशांति में उलझ जाए। भारतीय सेना सीमाओं पर सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम है, लेकिन आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति को संभालना उसके लिए कठिन होगा।

प्रदेश में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही लू सहित जलवायु संरक्षण को लेकर एक्शन प्लान बनाया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत वर्ष तीस मई को मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए कई अंतरिम निर्देश दिए थे। इसके साथ ही मामले को सुनवाई के लिए खंडपीठ में भेजा गया था। वहीं समान एकलपीठ ने गत दिनों एक बार फिर से इसी मुद्दे पर पुन: स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर मामले को जनहित याचिका के तौर पर सूचीबद्ध करने को कहा था।

राज्य भंडारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक और सहायक ...

- जैसा कि विदित है कि पिछली गहलोत सरकार के दौरान राज्य भंडारण निगम और श्री शुभम लॉजिस्टिक तथा उसकी सहायक कंपनी के बीच कृषि उपज के भंडारण और रख-रखाव के अनुबंधन में भारी अनियमितताओं के आरोप हैं। इस मामले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीएजी की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखा था।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी लिखा था जिसमें आरोप लगाए गए थे कि श्री शुभम लॉजिस्टिक अशोक गहलोत के करीबियों की कंपनी है, और इसी वजह से इस कंपनी को भण्डारण निगम से अनुबंधन कराकर 120 करोड़ से भी अधिक का फायदा पहुंचाया गया, दूसरी ओर इस अनुबंधन की वजह से राज्य भण्डारण निगम को 202 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ। कृषि मंत्री ने यह भी आरोप लगाया था शुभम लॉजिस्टिक और ओरिगो कमॉडिटीज़ इण्डिया ने अनुबंधन की शर्तो के विरूद्ध जाते हुए

भण्डारण निगम के गोदामों पड़ी 3000 करोड़ मूल्य की कृषि उपज को सुरक्षित करने के लिए बीमा नहीं करवाया था, जिससे खराबे या काला बाजारी की वजह से आम किसान और राज्य सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योकि अधिकतर कृषि उपज न्यूनतम मूल्य पर खरीदी गई थी।

राजस्थान राज्य भण्डारण निगम ने वाणिज्यिक कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा है कि करणी सिंह राठौड़, जो शुभम लॉजिस्टिक/ओरिगो कमॉडिटीज़ बनाम राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के बीच 2023 में चल रहे दो अलग-अलग विवाद में 'सोल आरबिट्रेटर' नियुक्त किये गए थे, यानि के.एस. राठौड़ को भली भांति पता था कि उन्हे नीति के विरूद्ध, एक ही वर्ष में, एक ही मसले में उलझी हुई पार्टियों के समक्ष दो अलग-अलग बार मध्यस्थता के लिए नियुक्त किए गए।

हैरानी की बात है कि मध्यस्थता करने के लिए नियुक्ति से पहले दिये गये 'डैक्लेरेशन" में भी के.एस. राठौड़ ने यह तथ्य उजागर नहीं किया, जो नियम-कायदों के विरूद्ध है।

हैरानी की बात है कि दो मामलों में के.एस. राठौड़ ओरिगो और शुभम लॉजिस्टिक के पक्ष में फैसला दिया और दूसरी ओर राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को 202 करोड़ रूपए की हानि पहुंचाने के दावे के मामले में दो वर्षों से फैसला नहीं दिया है, जबकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठकों, सी.ए.जी. की रिपोर्ट और विभागीय जांचों में यह स्पष्ट हो चुका है कि श्री शुभम लॉजिस्टिक तथा ओरिगो कमॉडिटीज़ इंडिया ने राज्य भण्डारण निगम के साथ हुए अनुबंधन की शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे भण्डारण निगम को भारी हानि हुई और दोनों कंपनियों को 120 करोड़ रूपये का अवांछनीय लाभ हुआ और साथ-साथ 3000 करोड़ से भी अधिक की कृषि उपज का बीमा नहीं कराकर किसानों की फसल और राज्य सरकार की संपत्ति को जोखिम में डाला गया।

उल्लेखनीय है कि पिछली गहलोत सरकार के अन्तिम वर्ष में के.एस. राठौड़ राज्य भण्डारण निगम और शुभम लॉजिस्टिक/ओरिगो कॉमोडिटिज से जुड़ सात मामलो में सोल आरबिट्रेटर नियुक्त किये गये थे। जिसमें उन्होंने राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को किसी भी आदेश में कोई राहत नहीं दी है, बल्कि उनके राज्य भण्डारण निगम के खिलाफ कुछ आदेशों को वाणिज्यिक कोर्ट ने खारिज किया है और अपील में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके आदेशों को पूर्णतया सही नहीं पाया।

महाकाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर बना है। इसी कंट्रोल रूम में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में आग बड़े क्षेत्र में फैल गयी। आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी बतायी जा रही है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908